# सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारसे १२ लाख ठगे

**रकम लेकर थमा दिया जल संसाधन विभाग का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आरोपित युवक सहित महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज**

भोपाल, (एजेंसी)। बिलखिरिया थाना इलाके में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक बेरोजगार से आरोपी सहित उसकी परिचित महिला द्वारा १२ लाख की ठगी किये जाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं शातिर आरोपी ने मेडिकल कराने के बाद उसे नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। इसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और मामला थाने जा पहुंचा। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस आरोपी और उसकी मददगार महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन सहित अन्य धाराओ में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नरेन्द्र छतरी रोड शिवपुरी निवासी बॉबी भार्गव पिता प्रेम प्रकाश भार्गव (२८) ने लिखित शिकायती आवेदन देते हुए बताया की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन दिनो वह सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहा था। चंबल इलाके में रहने वाली नंदिनी नाम की युवती से उसकी पहचान थी। बॉबी ने बातचीत के दौरान उसे नौकरी पाने की कोशिश किये जाने की बात बताई। इस पर नंदिनी ने उससे कहा कि उसका कपिल शर्मा नाम का परिचित युवक है जो सरकारी नौकरी पाने में उसकी मदद कर सकता है। बातचीत के बाद महिला ने बॉबी को कपिल शर्मा से मिलवा दिया। कपिल शर्मा ने भोपाल के बिलखिरिया थाना क्षेत्र में पारस सिटी में किराए का कमरा लिया हुआ था। वह यहां पर आता जाता था। मिलने पर उसने बॉबी को झांसा देते हुए कहा की उसकी जल संसाधन विभाग के कई बड़े अधिकारियों से खासी नजदीकियां है। और अपनी पहचान के जरिए वह बॉबी की नौकरी लगवा सकता है। इस पर बॉबी ने हामी भर दी, तब कपिल ने उससे कहा कि नौकरी के लिये उसे १२ लाख रुपए देना होंगे। बॉबी ने इस पर भी सहमति जता दी। इसके बाद बॉबी अपने परिजनों के साथ बीते साल जून २०२५ में कपिल शर्मा के पारस सिटी स्थित किराए के कमरे पर पहुंचा और उसे १२ लाख रुपए दे दिए। रकम लेने के बाद बॉबी का अपने विश्वास में लेने के लिये कपिल ने उसका मेडिकल भी करा दिया। और इसके बाद उसे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। बॉबी ने जब इस नियुक्ति पत्र की तस्दीक कराई तो वह फर्जी निकला। इसके बाद बॉबी ने सारी बात कपिल से मिलवाने वाली महिला नंदिनी को बताई तब वह कपिल का ही पक्ष लेने लगी। इसके बाद अपने साथ ठगी का अहसास होने पर बॉबी ने मामले की शिकायत थाने में कर दी। जॉच के आधार पर पुलिस ने कपिल व नंदिनी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शरू कर दी है।

## रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवालकी गला रेतकर हत्या

**दो दिन पहले रखा केयरटेकर फरार, उसी पर शक**

भोपाल, (एजेंसी)। राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके में रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की उनके घर में ही हत्या किए जाने की सनसनी सेहत घटना सामने आई है। उन्होंने दो दिन पहले ही एक व्यक्ति को हाउस हेल्प के तौर पर रखा था, अब वह लापता है. पुलिस का शक उसी नौकर पर है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश अग्रवाल बुधवार सुबह सूरजनगर स्थित उनके घर में उनका शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या की गई। वारदात के बाद घर में रखा गया केयरटेकर भी लापता है। पुलिस को उसकी भूमिका पर संदेह है, और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि राकेश अग्रवाल ने इस केयरटेकर को महज दो दिन पहले ही काम पर रखा था। उसे २८ सितंबर को पंजाब की एक एजेंसी के माध्यम से नौकरी पर रखा गया था। हत्या के बाद से केयरटेकर का कोई पता नहीं है। खास बात यह भी है कि उसका सामान भी घर में नहीं मिला, जिससे पुलिस को उसके वारदातके बाद फरार होनेका संदेह है।

# एसआईआके विरोधमें कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

**केंद्र की घोषणा के मुताबिक २४१० रुपए एमएसपी पर खरीदा जाए मक्का-जयवर्धन**

गुना, (एजेंसी)। गुना में एसआईआर के विरोध और विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बुधवार को एक विशाल पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस उग्र प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए गए और उन्हें गोरिल्ला की संज्ञा दी गई। रैली में एक कार्यकर्ता मैं हूं गोरिल्ला ज्ञानेश, वोट चुरा के करता ऐश लिखा हुआ पोस्टर और गोरिल्ला की पोशाक पहने नजर आया, जिसने सबका ध्यान खींचा।

कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को राष्ट्रपति के नाम एक १२ सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस ज्ञापन में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाकर उन्हें गिरफ्तार करने और उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई। साथ ही, ईसीआईनेट की जांच स्वतंत्र न्यायिक निगरानी में कराने की मांग भी रखी गई।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विधायक जयवर्धन सिंह ने गंभीर आरोप लगाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक षडयंत्र के तहत वोट चोरी करवाई है। एसआईआर के बहाने सोची-समझी साजिश के तहत देश के मूल नागरिकों के नाम काटे गए हैं, और कुछ नाम तो जानबूझकर हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा सॉफ्टवेयर लाया गया जिसके जरिए सीधे दिल्ली से नाम काटे जा रहे थे। अन्य चुनाव आयुक्तों ने इस पर छह से अधिक बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने यह षडयंत्र बेनकाब हो चुका है और राहुल गांधी तथा कांग्रेस के आरोप पूरी तरह सही साबित हुए हैं। ईवीएम में भी फजीर्वाड़ा कर चुनाव चुराया गया है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को देशभर में अपनी हार का खतरा सता रहा है, इसलिए ऐसे षडयंत्र रचे जा रहे हैं।

इस दौरान जयवर्धन सिंह ने गुना जिले में डीएपी खाद की भारी कमी का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि खाद के दलालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि शासन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं और सोसायटियों तक खाद नहीं पहुंच पा रही है। ई-टोकन व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जिन किसानों के पास वनाधिकार के पट्टे हैं, उनके लिए भी प्रशासन ने कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आश्वासन दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा, केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक मक्का की उपज का समर्थन मूल्य २४१० रुपए किसानों को दिलाने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। जयवर्धन सिंह ने कहा कि वर्तमान में कृषि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है, इसलिए उनसे मांग की जाए कि नवंबर से जनवरी तक मक्का की सरकारी खरीदी की जाए ताकि किसानों को उनकी उपज का सही और उचित दाम मिल सके। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं के हाथों में राहुल गांधी और जयवर्धन सिंह के बड़े-बड़े पोस्टर नजर आए और वक्ताओं ने सरकार को वोट, लोकतंत्र और खादका हिसाब देनेके लिए ललकारा।

# १५ दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बहोरीबंद जनपद अध्यक्ष

## मांग सुनने नहीं पहुंचा कोई अधिकारी, समर्थकों में आक्रोश

कटनी, (एजेंसी)। बहोरीबंद जनपद पंचायत अध्यक्ष लाल कमल बंसल विगत १५ दिनों से जनपद कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक शासन-प्रशासन का कोई भी अमला उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। प्रशासन की इस उदासीनता से जनपद अध्यक्ष और उनके समर्थकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल १६ सितंबर से अपनी मांगों को लेकर जनपद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में दर्जनों सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है।

धरने पर बैठे जनपद अध्यक्ष और उनके समर्थक जनपद सदस्यों की एक ही प्रमुख मांग है कि बहोरीबंद जनपद पंचायत में विगत ४ वर्षों से पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिषेक कुमार झा का तत्काल स्थानांतरण किया जाए। आरोप है कि सीईओ के कार्यकाल में जनपद पंचायत में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। पंचायतों के विकास कार्यों में जमकर अनियमितता हुई है, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों में भी भारी नाराजगी है। जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल का कहना है कि उन्होंने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को सीईओ की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन उन्हें अनिश्चितकालीन धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक सीईओ अभिषेक कुमार झा का स्थानांतरण नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना स्थल पर जनपद अध्यक्ष के साथ सरमन लाल चौधरी, प्रीतम गोंटिया, उत्तम लोधी, राधे यादव, सुरेंद्र सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जनपद सदस्य और ग्रामीण बैठे हुए हैं। धरने को विभिन्न सामाजिक संगठनोंका भी समर्थन मिल रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि १५ दिन से जनपद का प्रथम नागरिक धरने पर बैठा है, लेकिन कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ या किसी भी विभाग का अधिकारी मौके पर जाकर उनकी मांग सुनने तक नहीं आया। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर दिन-ब-दिन समर्थकों की भीड़ बढ़ती जा रही है।

## गांधी जयंती से ९ दिन चलेगा सेवा और स्वच्छता अभियान

**२ से १० अक्टूबर तक स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच, पौधरोपण और जरूरतमंदों की मदद पर जोर**

भोपाल, (एजेंसी)। गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में २ से १० अक्टूबर तक 'सेवा मेरा योगदान' अभियान चलाया जाएगा। नौ दिन के इस अभियान में जिला, विकासखंड, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की सेवा, सैनिक परिवारों का सम्मान और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद को भी शामिल किया गया है। अभियान की शुरुआत २ अक्टूबर को स्वच्छता कर्मियों के सम्मान, प्लास्टिक मुक्त परिसर का संकल्प और जागरूकता रैली से होगी। जल स्रोतों, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान किया जाएगा। लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग करने तथा वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी।

### स्वास्थ्य शिविरों में जांच और दवाओं की व्यवस्था

३ अक्टूबर को स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें लोगों की स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श और जरूरत के अनुसार दवाओं की व्यवस्था की जाएगी। ४ अक्टूबर को वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में विशेष कार्यक्रम होंगे। वृद्धजनों के साथ संवाद, भोजन, फल और दैनिक उपयोग की सामग्री का वितरण किया जाएगा। अनाथ बच्चों को कपड़े, जूते-चप्पल और स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य जांच और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी।

### जरूरतमंदों को चश्मे और दिव्यांगों को सहायक उपकरण

६ अक्टूबर को नेत्र परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। जरूरतमंद लोगों को चश्मे उपलब्ध कराने के साथ गंभीर मामलों में उपचार के लिए सहयोग किया जाएगा।

# डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे थे आठ कर्मचारी

## सीबीआई ने शुरू की जांच, पांच जबलपुर और तीन कटनी में हुए थे पदस्थ

जबलपुर, (एजेंसी)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने फर्जी दस्तावेजोंके माध्यम से डाक विभाग के विभिन्न पदों पर नौकरी करने वाले ८ कर्मचारियों के खिलापफ जांच आरंभ कर दी है। डाक ?वभाग ने इन सभी के दस्तावेजल जांच में पफजी पाए थे जिसके बाद इन सभी की सेवा समात कर दी है। सीबीआई दल ने इनमें से ५ आरोपियों को जबलपुर और ३ को कटनी से पकड़ा है। सीबीआई टीम की जांच चल रही है, जिसमें ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में कथित तौर पर फर्जी १०वीं की अंकसूची लगाकर नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दल के पास उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जांच में फिलहाल आठ अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, जबकि ३० से अधिक संदिग्ध नियुक्तियां भी जांच के दायरे में है।

दल के मुताबिक डाक विभाग में नियुक्त अभ्यर्थियों की १०वीं की अंकसूचियों का संबंधित शैक्षणिक बोर्डों से सत्यापन कराया गया था। जांच में इनमें सें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अंकसूचियां संबंधित बोर्डों द्वारा जारी नहीं किए जाने की जानकारी सामने आई थी। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि अलग-अलग अभ्यर्थियों ने विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक बोर्डों के नाम पर तैयार दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ दस्तावेज बिहार, झारखंड और जम्मू-कश्मीर सहित अलग.अलग राज्यों के बोर्डों से संबंधित बताए गए हैं। इस मामले में जबलपुर शहर के विभिन्न डाकघरों में इनकी पोस्टिंग थी।

इसमें मानवेंद्र सिंह, राजा बाबू अहिरवार, सौरभ शर्मा, प्रदीप कुमार और नयन कुमार सहित अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार मानवेंद्र सिंह को कुंडम, राजा बाबू और सौरभ शर्मा को पाटन, प्रदीप कुमार को उमरिया-बरेला तथा नयन कुमार को शाहपुरा क्षेत्र के डाकघर में पदस्थ किया गया था। इसके अलावा बद्री प्रसाद यादव, देवेन्द्र सिंह चौहान, रमाकांत शर्मा को भी विभाग में पदस्थ किया गया था। दस्तावेजों के सत्यापन में गड़बड़ी सामने आने के बाद डाक विभाग ने इन आठ अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं।

# नवरात्र बाद ४.५० लाख पेंशनर्स के हित में होगा आंदोलन

**५९ माह के एरियर्स पर पेंशनर्स में नाराजगी, कैशलेस इलाज और जनवरी २०२६ से २ प्रतिशत महंगाई राहत की भी मांग**

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में ५९ माह के बकाया एरियर्स के भुगतान की मांग को लेकर पेंशनर्स का असंतोष बढ़ता जा रहा है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने नवरात्रि के बाद मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। संगठन का कहना है कि छठवें और सातवें वेतनमान के ५९ माह के एरियर्स, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और लंबित महंगाई राहत का भुगतान नहीं होने से प्रदेश के करीब ४.५० लाख पेंशनर्स प्रभावित हैं। शिवाजी नगर में हुई पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की भोपाल जिला शाखा की बैठक में लंबित मांगों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलेभर से बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए। बैठक में पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि लंबित मांगों के निराकरण में शासन की ओर से लगातार देरी की जा रही है। संगठन के मुताबिक ५९ माह के एरियर्स का भुगतान किए जाने के बजाय इस मामले में कोर्ट से स्टे लेने के निर्देश की जानकारी सामने आने के बाद पेंशनर्स में नाराजगी और बढ़ी है। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स लंबे समय से छठवें और सातवें वेतनमान के बकाया एरियर्स के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले का जल्द समाधान निकालना चाहिए।

### कैशलेस इलाज और २ प्रतिशत महंगाई राहत भी मुद्दा

पेंशनर्स ने केवल एरियर्स ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स और उनके परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग भी दोहराई। इसके अलावा जनवरी २०२६ से लंबित २ प्रतिशत महंगाई राहत जारी करने की मांग की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि उम्रदराज पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च लगातार बड़ी चिंता बनता जा रहा है। ऐसे में कैशलेस उपचार की सुविधा से उन्हें सीधे राहत मिल सकती है।

### नवरात्र बाद मंत्रालय के सामने प्रदर्शन

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यदि सरकार ने पेंशनर्स की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो नवरात्रि पर्व के बाद भोपाल में मंत्रालय के समक्ष व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी पेंशनर्स के हित में लंबित मांगों पर निर्णय लेने का आग्रह करेगा। बैठक में मौजूद पेंशनर्स ने आंदोलन में संगठन का सहयोग करने और अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का संकल्प लिया।

# व्हाट्सएप पर दोस्ती कर तीन लाख हड़पे, क्रिप्टोकरेंसी का दिया झांसा

इन्दौर, (एजेंसी)। व्हाट्सएप के जरिए बने दोस्त ने क्रिप्टोकरेंसी देने के नाम पर अपने दोस्त से ३ लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया। पीड़ित दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है और व्हाट्सएप पर दोस्त बनें आरोपियों ने पहले अपने दोस्त को १० लाख रुपए की यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) ट्रांसफर कर उसका भरोसा जीता था। इसके बाद ३ लाख रुपए की क्रिप्टोकरेंसी देने का झांसा देकर नकद रुपए ले लिए और फिर सम्पर्क तोड लिया।

पुलिस के अनुसार पीड़ित सुनील चौधरी ने अपनी दर्ज शिकायत में बताया कि वह आरोपी प्रदीप बुक्कड़ को करीब तीन महीने से जानता है उससे उसकी पहचान वॉट्सऐप के जरिए हुई थी। सितंबर २०२५ में प्रदीप ने विक्की शर्मा से परिचय करा १० लाख रुपए की यूएसडीटी दी थी। क्रिप्टोकरेंसी मिलने के बाद उसे उन दोनों पर भरोसा हो गया था जिसके बाद २५ सितंबर को दोनों से वॉट्सऐप कॉल पर बातचीत हुई इस दौरान उन्होंने उससे कहा कि वे उसे ३ लाख रुपए की क्रिप्टोकरेंसी दे देंगे और उसे दशहरा मैदान बुलाया। बातचीत के बाद वह अपने दोस्त अभिषेक के साथ वहां पहुंचा तो विक्की मिला और उसने ३ लाख रुपए मांगे, जो उसने नकद दे दिए। इसके बाद विक्की उसे एक्सिस बैंक ले गया और मशीन में ५१ हजार रुपए जमा किए तथा कालानी नगर में ले जाकर वहां तीन अलग-अलग मशीनों में रुपए जमा करें। इसके बाद विक्की यह कहकर चला गया कि कुछ देर में उसके अकाउंट में २ लाख ९१ हजार रुपए की क्रिप्टोकरेंसी आ जाएगी। सुनील ने पुलिस को बताया कि इसके बाद वह काफी देर तक क्रिप्टोकरेंसी का इंतजार करता रहा जब विक्की से उसने बात की तो विक्की लगातार उसे टालता रहा इसके बाद जब उसने प्रदीप से संपर्क करने की कोशिश की तो फोन नहीं उठाया और फिर दोनों ने ही फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस ने प्रदीप बुक्कड़ और विक्की शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है।

# छह महीने से आयुष्मान योजना का भुगतान अटका

**सड़क पर उतरे निजी अस्पताल संचालक बोले- एनएबीएच की शर्त हटाओ**

भोपाल, (एजेंसी)। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कर रहे निजी अस्पतालों का भुगतान अटकने और अस्पतालों में एनएबीएच की अनिवार्यता के विरोध में बुधवार को निजी अस्पताल संचालक और डॉक्टर सडक पर उतर आए। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारी जेपी अस्पताल परिसर स्थित आयुष्मान योजना के कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। अस्पताल संचालकों ने पुराना बकाया भुगतान तत्काल जारी करने और एनएबीएच की अनिवार्यता हटाने की मांग की। अस्पताल संचालकों का कहना है कि कई अस्पतालों को पिछले पांच से छह महीने से नियमित भुगतान नहीं मिला है। कुछ अस्पतालों में इससे भी पुरानी राशि अटकी हुई है। भुगतान नहीं होने से दवा विक्रेताओं, कर्मचारियों और अन्य सेवा प्रदाताओं का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. धनंजय मिश्रा ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का करोड़ों रुपये का भुगतान लंबित है। उनका कहना है कि कई अस्पतालों पर औसतन डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक की राशि बकाया है। भुगतान नहीं मिलने से अस्पताल संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। डॉ. अंजन पाराशर ने कहा कि अस्पतालों और योजना के बीच हुए समझौते के अनुसार केस का भुगतान ४५ दिन में होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में भुगतान लगातार टुकड़ों में मिल रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जनवरी में १०० रुपये का काम होने पर २० रुपये और फरवरी में १०० रुपये के काम पर २० रुपये का भुगतान किया गया। इससे लंबित राशि लगातार बढ़ रही है। उनके अनुसार कई अस्पताल संचालकों ने कर्ज लेकर अस्पताल खड़े किए हैं। भुगतान अटकने से ऋण की किस्त, कर्मचारियों का वेतन और दवा-दुकानदारों का भुगतान तक प्रभावित हो रहा है।

### एनएबीएच की अनिवार्यता पर भी विरोध

निजी अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान योजना में एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) की अनिवार्यता का भी विरोध किया। उनका कहना है कि गुणवत्ता मानकों का विरोध नहीं है, लेकिन छोटे और मध्यम अस्पतालों पर एनएबीएच की अनिवार्यता व्यावहारिक नहीं है। डॉ. अंजन पाराशर ने दावा किया कि एनएबीएच प्रक्रिया में अस्पतालों को २५ से ३० लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। उनका कहना है कि जब पुराने भुगतान ही लंबित हैं, ऐसे समय में अस्पतालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना मुश्किल है। अस्पताल संचालकों के अनुसार एनएबीएच की शर्त पूरी नहीं कर पाने वाले छोटे और मध्यम अस्पतालों के आयुष्मान योजना से बाहर होने की आशंका है। इससे उन मरीजों पर असर पड़ सकता है, जो घर के नजदीक निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस उपचार कराते हैं।

### एक अक्टूबर से डी-एम्पैनलमेंट की आशंका

डॉ धनजय मिश्रा का कहना है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक अक्टूबर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बड़ी संख्या में अस्पतालों को आयुष्मान योजना से डी-एम्पैनल किए जाने की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में संबंधित अस्पतालों की अंतिम आधिकारिक सूची या आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। संचालकों का कहना है कि यदि बड़ी संख्या में अस्पताल योजना से बाहर होते हैं तो सरकारी और अन्य सूचीबद्ध अस्पतालों पर आयुष्मान मरीजों का अतिरिक्त भार बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसी भी बड़े स्तर की कार्रवाई से पहले अस्पताल संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।

# मेडिकल कालेज अस्पताल में ६ महीने की मासूम की मौत

जबलपुर, (एजेंसी)। रिसंभाग के सबसे बडे सरकारी अस्पताल नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में एक छह माह की मासूम बच्ची की मौत के बाद उसके परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति कि गठन कर दिया । प्राप्त जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जिसमें अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. पवन घनघोरिया और डॉ. रानू तिवारी मिश्रा को शामिल किया गया है।

# तालाबसे ५ किमी तक निर्माणपर पाबंदी, नजदीक बने सरकारी परिसरोंपर सवाल

**मास्टर प्लान-२०४७ में कैचमेंट संरक्षणके लिए सख्ती, अब बड़े सरकारी परिसरोंके निर्माण और जल निकासीके असरका आकलन भी जरूरी**

भोपाल, (एजेंसी)। बड़े तालाब के कैचमेंट को बचाने के लिए मास्टर प्लान-२०४७ के ड्राफ्ट में रातीबड़, नीलबड़ और फंदा से सीहोर सीमा की ओर करीब पांच किलोमीटर तक निर्माण पर पाबंदियां प्रस्तावित की गई हैं। इसका आधार सेप्ट, अहमदाबाद की २०१५ की रिपोर्ट को बनाया गया है। रिपोर्ट में बड़े तालाब का कैचमेंट करीब ३६१ वर्ग किलोमीटर माना गया है, जो सीहोर जिले तक फैला हुआ है।

ड्राफ्ट में प्राकृतिक जल बहाव और बारिश के पानी के तालाब तक पहुंचने को देखते हुए कैचमेंट क्षेत्र की दूर स्थित निजी जमीन पर भी निर्माण को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। इसके बदले ग्रीन टीडीआर जैसे विकल्प देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी कैचमेंट में तालाब से करीब ७०० मीटर की दूरी पर कई बड़े सरकारी और संस्थागत परिसर विकसित हो चुके हैं। ऐसे में अब सवाल इन परिसरों के निर्माण से जल निकासी और प्राकृतिक जल प्रवाह पर पडऩे वाले असर को लेकर भी उठ रहा है।

### २७५ से ३३० एकड़ में फैले बड़े परिसर

कैचमेंट क्षेत्र में भारतीय खेल प्राधिकरण, मप्र राज्य घुड़सवारी अकादमी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे संस्थान विकसित हैं। इन परिसरों का कुल क्षेत्रफल करीब २७५ से ३३० एकड़ बताया जा रहा है। इनमें सिर्फ भवन ही नहीं, बल्कि स्टेडियम, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, सडक़ें, पार्किंग और अन्य पक्की सतहें भी हैं। ऐसे में कैचमेंट संरक्षण के नए नियमों के बीच यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि निर्माण का आकलन केवल कुल जमीन के मुकाबले बने क्षेत्र के आधार पर होगा या बारिश के पानीके प्राकृतिक बहाव और जल निकासीपर पडऩे वाले प्रभावको भी मापा जाएगा।

### निजी जमीन पर सख्ती, सरकारी परिसरों पर अलग स्थिति?

मास्टर प्लान के प्रस्तावों में प्राकृतिक ढाल और जल बहाव को निर्माण नियंत्रण का आधार माना गया है। इसका सीधा असर कैचमेंट में आने वाली निजी जमीन पर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर, इसी जलग्रहण क्षेत्र में पहले से विकसित बड़े संस्थानों के मामले में मौजूदा निर्माण और भविष्य के विस्तार के लिए अलग-अलग मानदंडों की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि मास्टर प्लान में कैचमेंट संरक्षण के साथ पहले से विकसित परिसरों की स्थिति को भी स्पष्ट करना जरूरी माना जा रहा है। खासकर यह देखना होगा कि इन परिसरों में कितनी जमीन खुली है, कितनी पक्की है और बारिश का पानी किस तरह प्राकृतिक जल निकासी तंत्र तक पहुंचता है।

### पुराने मास्टर प्लान में भी था कैचमेंट

बड़े तालाब का कैचमेंट पुराने मास्टर प्लान में भी चिह्नित किया गया था। नए ड्राफ्ट में सेप्ट, अहमदाबाद की २०१५ की रिपोर्ट को आधार बनाकर कैचमेंट का विस्तृत दायरा तय किया गया है। टीएंडसीपी कमिश्नर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक पहले से बने सरकारी संस्थानों में उपलब्ध जमीन की तुलना में निर्माण क्षेत्र कम है। उन्होंने कहा कि टीएंडसीपी एक्ट के तहत शासन को समय की जरूरत के अनुसार मास्टर प्लान में संशोधन करने का अधिकार भी है।

# महंत बजरंग गिरि की मौत पर गुरु भाईने उठाये सवाल, लगाये साजिश के आरोप

## डेढ़ करोड़ की नकदी व सोना गायब होने का दावा, की जांच की मांग

भोपाल, (एजेंसी)। सतधारा आश्रम और सीहोर जिले की रेहटी तहसील स्थित रुद्रधाम रमगढ़ा आश्रम के संचालन व संपत्ति को लेकर जारी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। स्वामी परमहंस परमानंद गिरि के शिष्य सन्यासी योग विज्ञानानंद ने अपने गुरुभाई महंत बजरंग गिरि की मौत को संदिग्ध बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबध में भोपाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आश्रम से करीब १.५० करोड़ रुपए की नकदी और सोना गायब होने का भी दावा किया है। योग विज्ञानानंद के मुताबिक उनके गुरुदेव परमहंस परमानंद का स्वर्गवास ३० अगस्त को सतधारा आश्रम में हुआ था। इसके बाद गुरु-शिष्य परंपरा के अनुसार आश्रम की जिम्मेदारी से जुड़े घटनाक्रम के बीच महंत बजरंग गिरि की भी गुरु के देहावसान के १३वें दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका आरोप है, कि अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया। बजरंग गिरि के शरीर पर चोट के निशान होने की बात भी कही गई, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। विज्ञानानंद ने दावा किया कि गुरुजी के कमरे से ८० लाख रुपए नगद, करीब एक किलो